नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कॉर्डिनेटर ने सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-22 पर हस्ताक्षर किए

नीति आयोग के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत तथा संयुक्त राष्ट्र के भारत में रेजीडेंट कॉर्डिनेटर यूरी अफनासीव ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क (यूएनएसडीएफ) 2018-22 पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार, नीति आयोग के सदस्य और भारत में संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

यह करार सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयासों और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ.कुमार ने इस अवसर पर कहा कि 2018-22 का समय भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा होगा, क्योंकि 2022 में देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में यूएनएसडीएफ जैसा साझीदारी का दस्तावेज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यह 2022 तक गरीबी से मुक्त और सबके लिए समान अवसर वाले न्यू इंडिया के निर्माण के सपने को मूर्त रूप देने में सहायक होगा।

यूएनएसडीएफ सरकार के परामर्श से पहचाने गए प्रमुख विकास परिणामों की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम की रूपरेखा तैयार करता है और सरकार के परामर्श से चिन्हित की गयी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समन्वय स्थापित करता है। यूएनएसडीएफ को सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। यूएनएसडीएफ के संचालन के लिए नीति आयोग संयुक्तराष्ट्र के समकक्ष सरकार की प्रतिनिधि संस्था है। फ्रेमवर्क में प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा से निबटने की क्षमता, कौशल विकास, उद्यमित और रोजगार सृजन, लैंगिक समानता तथा युवाओं का विकास जैसे विषय शामिल हैं।

इन क्षेत्रों के अलावा संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दक्षिण- दक्षिण सहयोग में भी मदद करेगा। 2018-22 की अवधि में यूएनएसडीएफ के क्रियान्वयन के लिए करीब 11000 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसका 47 प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम को लागू करने के दौरान सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न स्त्रोतों से जुटाया जाएगा।

सीआरसी द्वारा इबी-5 इमिग्रेशन इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम अंतर्गत युएस सिटीजनशीप का मौका

अहमदाबाद : ध कोलोराडो रिजनल सेन्टर - युएस सिटीजन शीप एण्ड इमीग्रेशन सर्विसीस इबी-5 प्रोग्राम के मान्यता प्राप्त रिजनल सेन्टर द्वारा मुंबई में 12-13 अक्टूबर के दौरान 2 दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया हैं । सेमीनार में जिन भारतीयों को युएससीआईएस मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट - ध एम्पायर आउटलेट्स अंतर्गत निवेश द्वारा उन्हें, उनके पति/पत्नी, उनके 21 वर्ष से छोटे अविवाहित बच्चों के लिए युएस सीटीजनशीप का मौका मिलेगा । न्युयोर्क स्टेट एम्पायर आउटलेट्स फण्ड 1, एलएलसी, और सीआरसी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट न्युयोर्क सिटी का प्रथम और एक मात्र रिटेल आउटलेट प्रोजेक्ट हैं ।

युएस हंमेशा से ही भारतीयों के लिए माइग्रेट होने के लिए और स्थायी बनने का स्थान रहा हैं । कारकिर्दी के उतम मौके, हेल्थकेर, शिक्षा, समृध्ध अर्थतंत्र और उच्च जीवनधोरण वाले दुनिया के सबसे सफल अर्थतंत्र में भारतीयों ने सफलता और समृध्धि प्राप्त की हैं । प्रसिध्ध एच-1बी विजा में बदलाव आ रहे है और पसंदगी के नियम व शर्तें और कठोर बन रहे है तब भारत में इबी5 विजा लोकप्रिय बन रहा हैं ।-

येस बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में पुन: नियुक्त हुए श्री राणा कपूर

यह एमडी और सीईओ की पुन: नियुक्ति के विषय पर स्टॉक एक्सचेंज को 19 सितंबर, 2018 को जारी येस बैंक की विज्ञप्ति के संदर्भ में है।

सबसे पहले बैंक अपने शेयर धारकों को सूचित करना चाहता है कि बैंक और उसके एमडी और सीईओ को बैंक के निदेशक मंडल (25 सितंबर 2018 को निर्धारित बैठक), भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य योग्य शेयर धारकों द्वारा पूर्णतया निर्देशित किया जाएगा। बैंक का प्रबंधन अपने सभी शेयर धारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

2004 के मध्य में अपना परिचालन शुरू करने के बाद, पिछले 14 वर्षों से पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट जोखिम, लाभ प्रदाता, परिचालन दक्षता, वृद्धि आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण मानकों को लेकर बैंक का व्यापार और वित्तीय परिणामों के निरंतर वितरण का एक विस्तृत ट्रैक रिकॉर्ड है।(1-7)

जया प्रदा ने 28 सालों बाद &TV के 'परफेक्ट पति' में 'गोरी है कलाइयां' गाने का वही जादू चलाया

1979 में आई 'सरगम' फ्लिम से फ्लिमी दुनिया में प्रवेश करने से लेकर बॉलीवुड की खूबसूरत दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदान ने बॉलीवुड की दुनिया में अपना काफी नाम कमाया है। अपनी खूबसूरती और आकर्षक अंदाज से हमेशा ही फैन्स को अपने कदमों पर झुकाया है। उनके द्वारा निभाये गये अलग-अलग किरदारों के साथ 'आज का अर्जुन' फ्लिम के 'गोरी है कलाइयां' पर उनका मोहक डांस कई बार दोहराया गया और कई लोगों ने उसे पसंद भी किया।

वह एक बार फ्रि वही जादू, &TV के 'परफेक्ट पति' में चला रही हैं। महान अभिनेत्री जया प्रदा को बड़े ही जोश के साथ लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार द्वारा गाये गये इस गाने पर लगभग 28 सालों बाद थिरकते हुए नजर आयेंगी। इस शो में वह अपने बेटे पुष्कर (आयुष आनंद) और अपनी होने वाली बहू विधिता (सयाली संजीव) की शादी के खुशी के मौके पर यह डांस कर रही हैं। उन्होंने मैजेंटा रंग का जोड़ा और उससे मैच करते हुई बड़ी ही खूबसूरज ज्वैलरी पहनकर यह डांस किया और सारे कलाकार व क्रू उनका अंदाज देखकर हैरान रह गये। 56 साल की उम्र में भी उन्हें यह बखूबी मालूम है कि अपने सुंदर मूव्स और जोश के साथ कैसे दर्श्कों को आकर्षित किया जा सकता है। परदे पर चल रहे जश्न के इस मौके पर जया प्रदा ने अपने डांस से विविधता से भरी और सदाबहार गायिका लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन का तोहफ दिया। उनके डांस वाला यह एपिसोड लता मंगेशकर के जन्मदिन वाले दिन प्रसारित होगा। (19-8)

उत्पादन बढ़ाने व नस्ल सुधार में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी अत्यंत कारगर : श्री राधामोहन सिंह

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने उर्लिकंचन, पुणे स्थित बैफ में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी केंद्र के शिलान्यास समारोह और पुणे स्थित वेम्निकोम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आयोजित पोषक अनाज पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने भारतीय कृषि इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बैफ), पुणे में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी केंद्र के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए बताया कि भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी केंद्र योजना के अंतर्गत देश में 20 भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 19 केंद्रों के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा चुका है। इन केन्द्रों में 3 हजार देशी नस्लों के उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले सांड तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से दो केन्द्रों की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर एवं पुणे में किया जाना तय किया गया था जिसके अंतर्गत पुणे में इसका शिलान्यास किया जा रहा हैद्य

उन्होंने बताया कि देशी नस्लों के उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले सांडों के वीर्य के उत्पादन के लिए काफी मांग है। इसके साथ ही कुछ नस्लों की संख्या काफी कम हो गयी है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी बेहद कारगर साबित हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए बैफ, उर्लिकंचन में एक ऐसे ही केंद्र की स्थापना की जा रही है। केंद्र की स्थापना के लिए 5.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस केंद्र में उच्च अनुवांशिक क्षमता के गिर, साहिवाल, लाल कंधारी ,डांगी, देओनी और गओलाओ के सांड तैयार किए जाएंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु कृषि एवं डेयरी व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं। इसके लिए उत्तम नस्ल के पशुधन आवश्यक है, जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके मद्देनजर उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत लिंग चयनित वीर्य उत्पादन हेतु 10 वीर्य केन्द्रों को चिन्हित किया जा चुका है। दो केन्द्रों का प्रस्ताव उत्तराखंड, महाराष्ट्र के लिए भी स्वीकृत किया गया है जिसमें से उत्तराखंड के ऋषिकेश में लिंग चयनित वीर्य केंद्र का शिलान्यास जून 2018 में किया जा चुका है। वहीं, देशी नस्लों के जीनोमिक चयन हेतु इंडसचिप को विकसित किया गया है। इसके साथ ही 6000 पशुओं की इंडसचिप के उपयोग से जीनोमिक चयन के लिए पहचान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा मार्च, 2018 तक 29 राज्यों से आये प्रस्तावों के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 686 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 20 गोकुल ग्राम इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा पशु संजीवनी घटक के अंतर्गत 9 करोड़ दुधारू पशुओं की पहचान यूआईडी द्वारा की जा रही है। माननीय कृषि मंत्री ने कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीणों के दरवाजे पर लाभकारी स्व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बैफ के प्रयासों की सराहना करते हुए भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बैफ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की आशा व्यक्त की।

पुणे में ही स्थित वेम्निकोम में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पोषक अनाज उपमिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उदघाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि गेहूं, धान, मक्का आदि की अपेक्षा पोषक अनाजों (ज्वार, बाजरा, रागी व अन्य छोटे मिलेट) का विशेष महत्व है क्योंकि ये अनाज स्वास्थ्य एवं पोषण की दृष्टि से अति उत्तम हैं। पोषक अनाजों का उपयोग खाद्यान्न, पशुओं के चारे एवं दाने तथा ईंधन के रूप में होता है।

देश के सभी जिलों में आज से पशुधन की 20वीं गणना आयोजित की जाएगी

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सहभागिता से भारत के सभी जिलों में पशुधन की 20वीं गणना आयोजित की जाएगी। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे 1 अक्टूबर, 2018 से गणना का काम शुरू कर दें। इस अभिनव पहल की सफलता समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के पूर्ण सहयोग एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर है। यह गणना सभी गांवों और शहरी वार्डों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न परिवारों, पारिवारिक उद्यमों// गैर-परिवारिक उद्यमों और संस्थानों में जाकर वहां रखे जा रहे पशुओं (भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधा, ऊंट, कुत्ता, खरगोश और हाथी)/पोल्ट्री पक्षियों (मुर्गी, बतख, एमु, पेरू, बटेर और अन्य पोल्ट्री पक्षियों) की विभिन्न प्रजातियों की गिनती की जाएगी। 20वीं पशुधन गणना के तहत विशेष जोर टैबलेट/कम्प्यूटर के जरिए डेटा संग्रह पर होगा। जिसका लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह उम्मीद की जा रही है कि टैबलेटों के जरिए डेटा संग्रह से आंकड़ों की प्रोसेसिंग और रिपोर्ट सृजित करने में लगने वाला समय घट जाएगा।

तिरुपति में 100 उन्नत बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज आंध्र प्रदेश में तिरूपति में 100 उन्नत बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि 50 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल का नवीनीकरण और उन्नयन कर इसे लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तर वाला अस्पताल बना दिया गया है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड और पांच फ्लोर हैं। यह अस्पताल पूरी वातानुकूलित है, जिसमें विभिन्न विभागों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें ओपीडी, आईपीडी, वार्ड, आपातकालीन, नैदानिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनआईसीयू, सिटी स्कैन, एक्सरे और कई अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल के नवीनीकरण और उन्नयन से तीन लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को फायदा मिलेगा।

ईएसआई योजना की शुरूआत आंध्र प्रदेश के जुड़वां शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में 01.05.1955 में हुई थी। इसके बाद इस योजना को आंध्र प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया। 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 01 मई, 2016 से ईएसआई के विजयवाड़ा उप-क्षेत्रीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय में बदल दिया गया। इससे ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा का अधिकार क्षेत्र 01.05.2016 से आंध्र प्रदेश के सभी 13 जिलों तक बढ़ा दिया गया। केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के यनम क्षेत्र को भी आंध्र प्रदेश क्षेत्र से जोड़ दिया गया है।

ईएसआई योजना आंध्र प्रदेश के सभी 13 जिलों में पूरी तरह से लागू है और अभी राज्य में बीमित लोगों और ईएसआई लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 16.74 लाख और 64.96 लाख से अधिक है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में श्री सोमनाथ संस्कृत स्वर्ण पदक अर्पण गौरवशाली समारोह आयोजित

मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने संस्कृत भाषा को व्यापक फलक प्रदान करने के लिए विश्व के संस्कृत भाषा अभ्यासुओं को शोध-संशोधन और विशेषज्ञता के लिए सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी को केन्द्र बनाने का संकल्प जताया है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में अंग्रेजी तथा पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच संस्कृत और संस्कृति के जतन-संवर्धन की नितांत आवश्यकता है। संस्कृत भाषा के जतन और संवर्धन के लिए राज्य सरकार सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी को सम्पूर्णतया सहायता करेगी।

श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री सोमनाथ स्वर्ण पदक अवार्ड अर्पण समारोह में सम्बोधन करते हुए श्री रूपाणी ने कहा कि संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत हमारी संस्कृति का मूलाधार है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 के लिए डॉ. गौतमभाई पटेल और वर्ष 2018 के लिए डॉ. मणिभाई प्रजापति को सरदार स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में श्री सोमनाथ संस्कृत स्वर्ण पदक और 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए सोमनाथ युनिवर्सिटी की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसे आगे बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार संकल्पबद्ध है।

भाषा के संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने कक्षा 1 से आठ में गुजराती भाषा को अनिवार्य बनाया है। महाभारत, रामायण और गीता सहित तमाम पौराणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और यह इस भाषा के महत्व को दर्शाते हैं।

सोमनाथ मन्दिराउर भगवान सोमनाथ गुजरात की पहचान हैं। सोमनाथ ट्रस्ट श्री केशुभाई पटेल की अध्यक्षता में सोमनाथ मन्दिर के विकास के जो कार्य कर रहा है, जो सराहनीय है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री केशुभाई पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सोमनाथ मन्दिर राष्ट्रीय गौरव और गुजरात की अस्मिता का प्रतीक है। सोमनाथ ट्रस्ट ने इसकी स्थापना के समय संस्कृत की सेवा और संवर्धन करने का निर्णय लिया था। इसके उपलक्ष्य में आज वर्ष 2017 और 2018 के लिए श्री सोमनाथ संस्कृत स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं।

मात्र संस्कृत ही नहीं वरन इसके आसपास के पहलुओं को भी संशोधित करना आवश्यक है। नये शोध- संशोधन करने वालों को श्री पटेल और सोमनाथ ट्रस्ट ने आर्थिक सहायता सहित सभी प्रकार की मदद का आश्वासन दिया।

सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री पीके. लहरी ने कहा कि सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दो वर्ष बाद संस्कृत स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। संस्कृत और संशोधन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महानुभावों को यह अवार्ड प्रदान किये जाते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट की ट्रस्टडीड में देवभाषा और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का एक उद्देश्य दर्शाया गया है और उसी के अंतर्गत यह अवार्ड प्रदान किए जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ संस्कृत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले डॉ. मणिभाई प्रजापति और डॉ. गौतमभाई पटेल ने संस्कृत, इसकी विरासत और संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

इस स्वर्ण पदक अवार्ड समर्पण समारोह में सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, संस्कृत तथा संस्कृत भाषाप्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अमेजन एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर पर आकाशवाणी की प्रसारण सेवा का शुभारंभ किया

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नयी दिल्ली में अमेजान के एलेक्सा स्पीकर पर आकाशवाणी की प्रसारण सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रसारभारती के अध्यक्ष श्री ए सूर्यप्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाक्टर शशि शेखर वेमपति तथा अमेजान एलेक्सा एशिया के मुख्य टेक बिजनेस डेवलपमेंट अधिकारी श्री राजीव सहानी और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि अमेजान एलेक्सा जैसी सेवाओं ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। अलेक्सा पर आकाशवाणी की यह स्ट्रीमिंग सेवा एक तरह से संचार के पुराने और नए माध्यमों का अभिनव संगम होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे। वे विश्व के किसी के कोने में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकेंगे। श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि भविष्य में आकाशवाणी की अभिलेखीय सामग्रियों को भी ऐल्क्सा के प्लैटफार्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत के शहरी पुनरूद्धार को हरित और लचीला बनाने पर हरदीप पुरी का जोर

आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित और सतत् विकास हेतु व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उद्योग और समाज में स्व-नियमन लागू करने पर जोर दिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में 'प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एवं कचरा प्रबंधन-अवसर एवं चुनौतियां' विषय पर एक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत की विशाल शहरी पहल सोच-समझ कर किया गया एक ढांचागत निवेश है जो आगे सामाजिक सूचकांकों और पर्यावरणीय उद्देश्यों की दक्षता को भी जोड़ता है।

श्री पुरी ने भारत के शहरी पुनरूद्धार के हरित और लचीला बनाने की बात करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के साथ समझौता किए बिना हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में नये और वैकल्पिक तकनीकी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे न सिर्फ निर्माण लागत में कमी आ रही है, बल्कि इससे उत्सर्जित कार्बन में कटौती दिख रही है।

सम्मेलन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि कचरे के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन में भारत की क्षमता भविष्य में और बढ़ेगी, क्योंकि भारत में कचरा प्रबंधन अब भी मुख्य तौर पर इसके संग्रहण और न्यूनतम पृथक्करण के साथ निपटान के पारम्परिक तरीकों तक ही सीमित है।

जम्मू-कश्मीर में नयी पहल

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर 4-5 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक के अनुरूप राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख फैसला स्थानीय निकाय चुनाव कराना था जो अभी चल रहे हैं। केन्द्र सरकार चुनावों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय बलों की तैनाती के साथ राज्य सरकार को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। कई पहलुओं से इन स्थानीय निकाय चुनावों का ऐतिहासिक महत्व होगा। ये चुनाव जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करेंगे जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2005 के बाद और पंचायत चुनाव 2011 के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायतों के सरपंचों के लिए प्रत्यक्ष चुनावों का प्रावधान जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बहाल कर दिया गया है। इन चुनावों के जरिए विधिवत गठित स्थानीय निकायों के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा लगभग 4,335 करोड़ रूपए के केंद्रीय अनुदान का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनाव नहीं होने से जम्मू-कश्मीर के लोग उनके कल्याण के लिए मिलने वाली इस सहायता से वंचित हो जाते।

संविधान के 73 वें संशोधन के तहत पंचायतों को स्थानांतरित सभी 29 विषयों से संबधित कार्यों और पदाधिकारियों को भी जम्मू-कश्मीर के पंचायतों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी जैसे केन्द्रों में भी किया जाएगा। पंचायतों की वित्तीय शक्तियां 10 हजार रुपये से 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही हैं। ब्लॉक काउंसिल के लिए इसे 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जा रहा है। पंचायतों को अपने स्तर पर धन राशि जुटाने की शक्तियां भी दी जा रही हैं। इनमें भवन शुल्क, मंनोरंजन कर, विज्ञापन, होर्डिंग तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और पेशों से वसूल किए जाने वाली आय शामिल होगी। केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से मनरेगा, प्रधांन मंत्री आवास योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा और मध्यान्ह भोजन आदि जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय मदद पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर जुटाई गयी राशि की पूरक बनेंगी। विभिन योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान के अलावा पंचायतों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा, बागवानी विकास, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन से भी जोड़ा जाएगा। इन योजनाओं को लागू करने के लिए औसतन प्रत्येक पंचायत को प्रति वर्ष 50-80 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायतों को और मजबूत बनाने के लिए एकाउंटेंट, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और ब्लॉक पंचायत इंस्पेक्टर आदि के अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी जा रही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

ई-प्रोक्योरमेंट के द्वारा — भण्डार विभाग

निविदा सूचना संख्या : एस/2018/27 — दिनांक : 27.09.2018

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रधान मुख्य सामग्री प्रबन्धक, तृतीय तल, उ0प0रेलवे प्रधान कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर-302017 निम्नलिखित मदों हेतु मोहरबंद खुली ई-निविदायें www.ireps.gov.in में सभी खुली ई-निविदायें 14.25 बजे बंद कर दी जायेगी।

संशोधन

निविदा सूचना संख्या	निविदा संख्या	विवरण	
		पूर्व में	अब
एस/2018/24 दिनांक : 31.08.2018	70185054	04.10.2018	24.10.2018

(1) इच्छुक निविदाकर्ता हमारी बेवसाईट पर सामग्री का पूरा विवरण/स्पेसिफिकेसन/बयाना राशि/निविदा फार्म का मूल्य और अन्य जानकारी देख सकते है। सभी निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि अपने डिजिटलहस्ताक्षर प्राप्त करे तथा अपनी फर्म को उक्त साइट पर रजिस्ट्रर्ड करे। (2) 25 लाख से नीचे के विज्ञापित निविदा, सीमित निविदा, विशेष सीमित निविदा एवं कम मूल्य की निविदा में भाग लेनें के लिए /देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.ireps.gov.in पर जायें। (3) कोई भी जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.nwr.indianrailways.gov.in पर देख सकते हैं। (4) 01 जुलाई 2017 से सेवा व माल कर (GST) लागू किया गया है। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाऐं भरने हेतु अपनी फर्मों को सेवा व माल कर (GST) से पंजीकृत करे एवं तदनुसार निविदाओं (Tenders) की दरें (Rates) भरें। 1005-PA/18

हमें /NWRailways पर फॉलो करें